ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

बारिश की बूंदें बचाकर हजारों परिवारों ने पाई खतरनाक पानी से मुक्ति

रविवारीय, 23 - 29 मई 2021 वर्ष- दो, अंक-42, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

लॉकडाउन में कड़ाई से हमें कोरोना के ख़िलाफ़ मिल रही है सफलता :मुख्यमंत्री

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत पहले आंशिक लॉकडाउन एवं अभी किए जा रहे कड़ाई से हमें कोरोना के ख़िलाफ़ संघर्ष में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। जीविका और जीवन के इस लड़ाई में हम पूरी सावधानी से दोनों को बचाने हेतु कार्य कर रहे हैं एवं ज़रूरत पड़ने पर कड़े फ़ैसले लेने से भी नहीं हिचक रहे हैं।शहरों में जहां हमें कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने में सफलता मिली है वहीं अब सरकार ज़्यादा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित करने पर है।

तीसरे लहर की हकीकत

वरीय संवाददाता

साल 2000 में जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था तब किसी ने उसे पहली लहर नहीं कहा था। साल 2000 के आखिरी तिमाही में जब कोरोना काबू में आ गया था तब सरकार से लेकर आम लोगों ने राहत की सांस ली थी और ये मान लिया गया कि कोरोना अब देश में खत्म हो चुका है। तब कुछेक खबरों और लेखों में कोरोना के दूसरे हमले की आशंका जतायी गयी थी और सौ साल पहले फैले वैश्विक स्पेनिश फ्लू महामारी का हवाला देकर बताया गया था कि उस वक्त भी एक बार महामारी काबू में आ गयी थे और लोग लापरवाह हो गये उसके बाद स्पेनिश फ्लू का दूसरा दौर शुरू हुआ जिसमें पहले से भी ज्यादा लोग हताहत हुये।

आज भारत में कोविड-19 का दूसरा लहर जारी है। लाखो लोग काल के गाल में असमय समा गये और सबसे दुखद कि इस बार युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। यानि महामारी का जो इतिहास रहा है वह फिर दुहराया गया। आंकड़ों की माने तो कोरोना के दूसरे लहर का पीक भी अब समाप्ति पर है। लेकिन इससे भी बड़े खतरे तीसरे लहर की आशंका जतायी जा रही है। यह चर्चा अब जोरों पर है कि पहले लहर में कोरोना ने बुजुर्गों की जान ली दूसरे लहर में युवा निशाने पर रहे और अब कोविड-19 वायरस खुद को म्यूटेंट करके इस बार बच्चों पर हमलावर होगा?क्या सचमुच ऐसा कोई खतरा देश पर मंडरा रहा है ?

डरा रही है तीसरे लहर की भविष्यवाणी

अभी तीसरे लहर की भविष्यवाणी कुछ इस तरह से की जा रही है जिससे और ज्यादा भय पैदा हो जा रहा है। दूसरे लहर को देख कर ज्यादतर जानकारों ने भी इसे इस तरह से प्रस्तुत किया है कि लोग, सरकारें सतर्कता के बजाय चिंतित ज्यादा हो रहे हैं। ज्यादतर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिये खतरनाक होगी और हमें बच्चों के लिये वैक्सीन बनाने पर सारा जोर लगाना चाहिये। ये लहर कब आएगी इसका ठीक अंदाज़ा लगा पाना अभी मुश्किल है लेकिन डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हो सकती है।कोरोना की पहली लहर में टेस्ट में चार फ़ीसद बच्चे पॉज़िटिव पाए गए थे और दूसरी लहर में ये संख्या 10 प्रतिशत तक पहुँच गई है।आबादी के हिसाब से देखा जाए तो देश में बच्चों की 30 करोड़ की आबादी का ये 14 प्रतिशत होगा।इंडियन काउंसिल फ़ॉर मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने फ़रवरी 2021 की अपनी सीरो रिपोर्ट में कहा था कि 25.3 फ़ीसद बच्चों में वायरस के एंटीबॉडी मौजूद थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 25.3 फ़ीसद बच्चों को कोरोना संक्रमण हो चुका है .जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर वी. रवि ने बीबीसी को बताया, "अगर पहली और दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण के आंकड़ों और सीरो सर्वे के आंकड़ों को मिला कर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि भारत में 40 फ़ीसदी बच्चे कोरोना वायरस के संपर्क में आ चुके हैं।

इन सारे भयावह आंकड़ो और आशंकाओं के बीच ये बात तो तय है कि सरकार तैयार रहे, आम लोग संक्रमण से बचाव में सतर्क रहें साथ ही वैक्सीनेशन को युद्धस्तर पर किया जाये तो तीसरी लहर को भारत झूठला देगा, आखिर पहली लहर में इस पर हमने सफलता पायी ही थी?

थर्ड वेव आयेगा ही नहीं बशर्ते?

जब दूसरा लहर काबू में आ रहा है तो अभी मिले समय को कीमती मान कर सरकारें वैक्सीनेशन में तेजी लायें, लोग पीक के समय जैसी ही सतर्कता बरतें, अस्पतालों में सारी व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाये, प्रभावी दवाओं का स्टॉक तैयार रहे ताकि कालाबाजारी और जमाखोरी न हो, केंद्र से लेकर राज्य सरकारें और जनता प्रमाद से दूर रहे। तो तीसरी लहर को हम आने से पहले ही रोक लेंगे।

आखिर यही सारी गलतियां हमने की और दूसरे लहर को न्यौता भी दिया।

यूरोप को देख सीखते तो दुसरी लहर आती ही नहीं

जब साल 2000 में कोविड का फैलाव भारत में हुआ उस वक्त यह दुनिया के कई देशों में तबाही मचा चुका था। उसके बाद इसका संक्रमण भारत में हुआ। तब तक भारत कुछ हद तक सचेत हो चुका था। केंद्र सरकार ने समय रहते संपूर्ण लॉक डाउन लगा दिया। इससे लोगों को तकलीफें तो हुयीं , पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तब इस लॉक डाउन ने भारत में भयावह स्थिति पैदा होने के खतरे को बहुत हद तक टाल दिया था।

तब तक न तो कोरोना कि कोइ दवा थी, न कारगर टेस्टिंग किट न वैक्सीन। इसके बावजूद दुनिया के अन्य प्रभावित देशों से तुलना करें तो भारत में पहले दौर में मौतों के आंकड़े कम थे। सरकारी सख्ती, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों की भयावहता को देख कर लिये गये सबक ने तब भारत को बड़े नुकसान से बचा लिया था। साल 2000 के अंत तक भारत में कोरोना को लोग भूल कर लापरवाह हो चुके थे। उधर कोरोना के नये वेरियेंट से तबाही ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों में दूसरे दौर के रूप में जारी थी। यहीं पर हम चुके गये। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, हमारा मेडिकल सेक्टर और जनता सभी आश्वस्त थे कि देश में अब यूरोप की तरह कोरोना की कोई दूसरी लहर नहीं आयेगी। लेकिन यह चूक भारी पड़ी नया स्ट्रेन अंतत: भारत में प्रवेश कर गया और यहां के लोगों पर कहर बन कर टूटा।

अगर हम पहले दौर की समाप्ति के बाद लापरवाह न होते, प्रमाद से दूर रहते तो संभवत: दूसरा दौर भारत में आता ही नहीं। जब यूरोप में नये वेरियेंट ने तबाही मचायी तो हमें उसी वक्त सतर्क हो जाना था। पहले से ही वैक्सीनेशन को गति दी गयी होती, ऑक्सीजन उत्पादन से लेकर वेंटिलेटरों का इंतजाम वक्त पर कर लिया जाता, तो दूसरे लहर को शुरूआती हमले के बाद ही काबू में किया जा सकता था। अफसोस दूसरी लहर के जिम्मेदार हम सभी हैं सिर्फ सरकार नहीं।

आखिर पत्रकार कोरोना वारियर्स क्यों नही!

पूरे देश में पत्रकारों की मौत कोरोना महामारी से हो रही है। पत्रकार प्रशासन के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर लोगों के बीच लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए प्रशासन के हर संदेश को जग जाहिर करने के लिए दिन रात सड़कों पर घूमते हैं । अपने परिवारों, अपना बिना ख्याल किए की उनका क्या होगा। उसके बावजूद उनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था ना होना काफी शर्मनाक और दुख दायक है। यहां तक कि उन्हें कोरोना वारियर्स भी ना समझना वाकई शर्मनाक है। मैं पूछना चाहता हूं पत्रकारों के एसोसिएशन से जो कहते हैं कि हम पत्रकार के हक की लड़ाई के लिए लड़ते हैं क्या उन्होंने कभी सरकार या स्थानीय प्रशासन से मांग की। क्या चौथा स्तंभ होने वाला पत्रकार जो स्थानीय प्रशासन या सरकार की हर एक निर्णय या यूं कहें तो सरकार और प्रशासन की हर एक बातों को जनता तक पहुंचाने का काम पत्रकार अपने पत्रकारिता के द्वारा करता है। चाहे जागरूक करना हो या किसी प्रकार की खबरों को विस्तार पूर्वक जनता के समक्ष रखना हो सब में पत्रकार की अहम भूमिका होती है। इसके बाद भी इन्हें कोरोना वारियर्स न समझना और इनके लिए टिका न उपलब्ध कराना कहाँ तक जायज है? कभी किसी एसोसिएशन ने इसकी मांग क्यों नही की या यूँ कहे तो इसकी चर्चा भी कभी क्यों नही की ?

अगर सरकार और प्रशासन हम पत्रकारों के लिए सो गई तो क्या हमारे हक की लड़ाई लड़ने का प्रण लेने वाला संगठन भी सो गया है या वह अपने कार्यों को भूल गया है। संगठन में तो वरिष्ठ पत्रकार ही हैं क्या उनको नही पता कि किस तरह उनके साथी कार्य करते है। उसके बाद भी क्यों सोये हुए है या चुप्पी धारण किये हुए हैं। आज वैशाली जिला का पत्रकारिता जगत और समाज ने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिन्होंने हमेशा समाज ले लिए कार्य किया है। आज इनकी मौत भी कोरोना ने ली है। इनके लिए कोई व्यवस्था नही हो पाई। उस व्यकि को जिन्होंने हमेशा मुस्कुराना सीखा और खुद ही नहीं दूसरों को भी मुस्कुरा देने का कार्य करने वाले वरिष्ठ पत्रकार और वैशाली जिला के प्रभात खबर समाचार पत्र के ब्यूरो और बड़े भाई सुनील कुमार सिंह जो अपने जीवन को पत्रकारिता जगत के लिए समर्पित कर दिया। आज उनकी दुखदाई मौत झकझोड़ दी है। उनका अंतिम समय में सही से इलाज ना हो पाना भी काफी अशोभनीय था। मैं सरकार स्थानीय प्रशासन या फिर संगठन की बात ना करते हुए मैं बात करता हूं उन बड़े-बड़े मीडिया हब के मालिकों की। आखिर उनलोगों ने भी क्यों नही पत्रकारों के लिए सरकार से उनके लिए इस कोरोना काल मे कुछ मामूली व्यवस्था की मांग की। आखिर क्यों पत्रकारों के साथ ऐसे घटना घट रही है । मैं पत्रकारिता जगत का काफी छोटा सिपाही हूँ हमसे बड़े-बड़े काफी योद्धा इस पत्रकारिता जगत में मौजूद हैं मैं उनसे और पत्रकारों के लिए लड़ने वाले संगठनों से निवेदन करता हूँ कि आगे आकर हमारे इस आवाज को या यूं कहें तो अपने हक की आवाज को आगे करने की कोशिश करेंगे। आपका साथी **नलिनी भारद्वाज**

ब्यूरो चीफ(वाणीश्री न्यूज)ब्यूरो वैशाली (जनमत की पुकार)
राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य(वेव जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया)

ताउ ते के तबाही के बाद अब यास आगे गुलाब तूफान से पार पाना होगा

एजेंसियां

चक्रवात यास के चलते मौसम विभाग की मछुआरों को बंगाल की खाड़ी से निकलने की चेतावनी जारी गयी है। चक्रवाती तूफान "तौकते" या "ताउते" ने भारत के दक्षिणी हिस्सों और गुजरात में काफी जान-माल का नुकसान किया। यह तूफान भीषण था और इससे विनाश को उन क्षेत्रों में देखा जा सकता है जहां से यह गुजरा और जहां यह टकराया। अब एक और "यास" नाम का चक्रवात भारत की ओर बढ़ रहा है, इस बार इसकी चपेट में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आने की आशंका है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 22 मई, 2021 के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और इससे सटे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके 24 मई 2021 तक एक चक्रवाती तूफान "यास" में तब्दील होने का अनुमान लगाया गया है। इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 26 मई की सुबह के आसपास ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट पर

पहुंचने की आशंका जताई गई है। यदि यह चक्रवाती तूफान "तौकते" या "ताउते" जैसा खतरनाक होता है तो पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इसके तबाही मचाने के आसार हैं। इसका असर झारखंड पर भी होना बताया जा रहा है।

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इस चक्रवात के 26 मई के आसपास ओडिशा-बंगाल तट पर टकराने के आसार हैं, जो उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों को अधिक प्रभावित कर सकता है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने फसलों को बचाने की तुरंत सुरक्षा और निवारक उपाय करें।

इस तूफान के बाद बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में आनेवाले तूफान का नाम गुलाब होना बताया जा रहा है। इस बार नामकरण की बारी पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। दक्षिण-पश्चिम अरब सागर और इससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश के तटों पर 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के 60 किमी प्रति घंटे की गति तक पहुंचने की आशंका है। यह गतिविधि पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर में जारी रहने का अनुमान है, मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि इन इलाकों में मछली पकड़ने तथा किसी तरह के व्यापार से संबंधित काम के लिए जाने से बचें।दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में और तमिलनाडु - आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तट पर हवाओं के 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर में 55-65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के 75 किमी प्रति घंटे की गति तक पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि इन इलाकों में मछली पकड़ने तथा किसी तरह के व्यापार के काम के लिए जाने से बचें।

सीसीएल में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया

संवाददाता :सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय, डॉ अनिल कुमार जैन द्वारा कोल इंडिया एवं सभी अनुषंगी कंपनी सहित सीसीएल को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सभी को आतंकवाद विरोधी दिवस 2021 का 'शपथ'दिलवाया गया। इस अवसर पर सीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद, निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह, निदेशक (वित्त) एन.के. अग्रवाल, एस.के. श्रीवास्तव एवं विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष वर्चुअल के माध्यम से शपथ कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही क्षेत्रीय कर्मियों ने भी वर्चुअल के माध्यम से शामिल हुये। कार्यक्रम कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुये किया गया।आज आतंकवाद वर्तमान परिपेक्ष्य में पूरे विश्व में सबसे बड़ी चुनौती है, इससे निपटने व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई के लिए जागरूकता हेतु प्रत्येक वर्ष21मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है ।

यास ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार

रांची :चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए रांची रेल मंडल से खुलने वाली /होकर चलने वाली सात ट्रेनों के अतिरिक्त चार ट्रेनें रद्द रहेंगी।

- ट्रेन संख्या 02803 रांची - हावड़ा स्पेशल ट्रेन दिनांक 25/05/2021 एवं दिनांक 26/05/2021 को रांची से रद्द रहेगी।
- ट्रेन संख्या 02804 हावड़ा - रांची स्पेशल ट्रेन दिनांक 25/05/2021 एवं दिनांक 26/05/2021 को हावड़ा से रद्द रहेगी।
- ट्रेन संख्या 02896 रांची - हावड़ा स्पेशल ट्रेन दिनांक 26/05/2021 को राँची से रद्द रहेगी।
- ट्रेन संख्या 02895 हावड़ा - रांची स्पेशल ट्रेन दिनांक 26/05/2021 को हावड़ा से रद्द रहेगी ।

पहले से रद्द सात ट्रेनों की सूची

- ट्रेन संख्या 08451 हटिया - पुरी स्पेशल ट्रेन दिनांक 25/05/2021, दिनांक 26/05/2021 एवं दिनांक 28/05/2021 को हटिया से रद्द रहेगी ।
- ट्रेन संख्या 08452 पूरी - हटिया स्पेशल ट्रेन दिनांक 25/05/2021, दिनांक 26/05/2021 एवं दिनांक 27/05/2021 को पूरी से रद्द रहेगी ।
- ट्रेन संख्या 02814 आनंद विहार - भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन दिनांक 24/05/2021 को आनंद विहार से रद्द रहेगी।
- ट्रेन संख्या 02875 पूरी - आनंद विहार स्पेशल ट्रेन दिनांक 25/05/2021 को पूरी से रद्द रहेगी ।
- ट्रेन संख्या 02876 आनंद विहार - पूरी स्पेशल ट्रेन दिनांक 25/05/2021 को आनंद विहार से रद्द रहेगी ।
- ट्रेन संख्या 02823 भुवनेश्वर - नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन दिनांक 25/05/2021 को भुवनेश्वर से रद्द रहेगी ।
- ट्रेन संख्या 02824 नई दिल्ली - भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन दिनांक 26/05/2021 को नई दिल्ली से रद्द रहेगी ।

खेतों में काम बढ़ने से महिलाओं के पोषण पर असर

शहाना घोष

खेती के काम में महिलाओं का योगदान पुरुषों के बराबर ही है। पर घरेलू काम का बोझ सिर्फ महिलाओं के जिम्मे होता है। काम के इस दोहरे बोझ की वजह से उनका पोषण प्रभावित हो रहा है।

इस विषय पर महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में एक शोध किया गया जिसमें सामने आया कि खेती का काम जब सबसे अधिक होता है तब महिलाएं कुपोषण का शिकार भी अधिक होती हैं। खेती के काम में शामिल महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार को नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत है।

घरेलू काम के साथ खेती का काम संभालने वाली महिलाओं पर काम का बोझ कम हो इसके लिए ऐसी तकनीकी के ईजाद की जरूरत है जो महिलाओं का बोझ कुछ कम हो सके। भारत के खेतों में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। लेकिन घरेलू काम निपटाने जैसी पारंपरिक चुनौती हो या बदलते मौसम जैसी नई

चुनौती- महिलाओं की मुश्किल पुरुषों से अधिक ही रहती हैं। यह जग-जाहिर है कि महिलाओं की जिम्मेदारी सिर्फ खेत में काम करने भर से समाप्त नहीं होती, बल्कि ये महिलाएं खेतों के अलावा घर के काम भी संभालती हैं। दोहरी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में इन्हें अपनी सेहत का ख्याल नहीं रहता। एक अध्ययन में सामने आया है कि खेती के मौसम में-बुआई से लेकर फसल कटाई तक- महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ जाता है। इस दौरान उनके शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता।

इस अध्ययन में खेती में योगदान देने वाली महिलाओं पर काम की अधिकता की वजह से होने वाले कुप्रभावों को सामने लाने की कोशिश की गयी है। भारत में खेती के काम में लगी श्रमशक्ति का एक तिहाई से अधिक हिस्सा महिलाओं का है। अध्ययन के नतीजों ने इस बात की वकालत की है कि नीति-निर्माण के जरिए महिलाओं के ऊपर से अतिरिक्त भार कम किया जाए, ताकि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बीच उनके सेहत का ख्याल रखा जा सके। ग्रामीण भारत में महिलाएं अपना 32 फीसदी समय खेती से संबंधित गतिविधियों पर खर्च करती हैं। इसके अलावा उनका दिन का औसतन 300 मिनट ऐसे काम में खर्च होता जिसकी अक्सर गणना नहीं होती। यह काम है घर का काम। खाना बनाने से लेकर साफ-सफाई, घर-परिवार और बच्चे-बुजुर्गों की देखभाल। हालांकि, यह आंकड़ा किसी सामान्य दिन का है।

खेतों में जब काम बढ़ता है तो महिलाओं पर इसका बोझ बढ़ता ही जाता है। खेती के काम में महिलाएं लगभग पुरुषों के बराबर ही समय देती हैं, लेकिन जब घर का काम जोड़ दें तो महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक समय काम करते हुए बिताती हैं।जब महिलाएं खेतों में काम करती हैं तो इस काम से उन्हें मजदूरी मिलती है। हालांकि, ऐसा घरेलू काम में नहीं होता। खेती का काम जब बढ़ता है तो मजदूरी न खोने की चाह में महिलाएं खेती के काम में अधिक समय व्यतीत करती हैं। बावजूद इसके घर का काम कम नहीं होता।

इस दौरान महिलाएं खुद का ध्यान नहीं रख पाती। उनके शरीर में पोषण के जरूरी तत्व जैसे कैलोरी, प्रोटीन, वसा, आइरन और जिंक की कमी होती जाती है। एक गणना की है जिसमें दिखता है कि अगर महिला खेती के काम में 100 रुपए कमाती हैं तो उनके पोषण में 112.3 कैलोरी,0.7 एमजी जिंग, 0.4 एमजी जिंक, और 1.5 ग्राम प्रोटीन की कमी होती है।

कुछ राज्य सरकारों ने अपनी नीतियों में महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया है लेकिन यह नाकाफी है। सिर्फ समय की बचत करना ही काफी नहीं, बल्कि उनके पोषण का पूरा ख्याल रखना भी जरूरी है, अध्यनकर्ताओं ने माना। इस कमी को दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में अनाज के अलावा दूसरे पोषक आहार भी शामिल किया जा सकता है।

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

अक्षम्य अपराध है टीके की बर्बादी

याद किजिये साल 2020 में जब कोविड 19 की न तो कोई दवा थी न ही कोई जांच का पुख्ता उपकरण। उस वक्त जब जांच का देसी किट बना तब वह भी बड़ी उपलब्धि थी। तब टीके का आविष्कार दूर की कौड़ी लग रही थी। आज जब भारत में कोरोना के ठीके का आविष्कारऔर उत्पादन हो रहा है तो इसकी बर्बादी किसी अपराध से कम नहीं।

टीके के एक शीशी के खुलने पर दस लोगों को डोज लगाया जा सकता है। कहीं तो टीके की कमी है और कई जगहों पर ऐसा भी हो रहा है कि दस लोग नहीं हो पा रहे हैं ताकि एक शीशी का पूरा उपयोग हो सके। क्योंकि शीशी खुलने के बाद उसमें बचा हुआ डोज बर्बाद हो जाता है।

यह दुर्भाग्य है कि भारतीय टीके को जिसे बहुत ज्यादा कोल्ड स्टोरेज की भी आवश्यकता नहीं उसे भी इतने बड़े देश में लापरवाही और रख रखाव में कमी के कारण बर्बाद किया जा रहा है।

हमारे टीके का क्या महत्व है आप इसी से समझ लें के दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से देश को महज एक लाख टीके भेजे गये और वहां की जनता भारत के जय जयकार में लग गयी। और स्वयं भारत में लाखो लोगों के लायक टीके बर्बाद हो चुके हैं।

देश में अब तक लगभग 18 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। जहां अभी भी देश की एक बड़ी आबादी का टीकाकरण करना बड़ी चुनौती है, वहीं लगातार टीके की बर्बादी सरकार के लिए चिंता का कारण है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकों की बर्बादी रोकने के लिए केरल की तारीफ की और कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूत करने के लिए वैक्सीन की बर्बादी कम करना सबसे अहम है। यह पहला ऐसा अभियान है, जिसके तहत समूची वयस्क आबादी का टीकाकरण होना है। देश में कोविड टीके की औसतन 6.5 फीसद खुराक बर्बाद हो रही है। पिछले दिनों हरियाणा में 2.29 लाख लोगों को लगाई जा सकने वाली वैक्सीन बेकार चली गई।

दुख की बात है कि वैक्सीन बर्बादी के मामले में तमिलनाडु, हरियाणा, असम, पंजाब, मणिपुर और तेलंगाना सबसे आगे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों से यह जानकारी मिली है कि तमिलनाडु वैक्सीन बर्बादी की सूची में शीर्ष पर है। यहां अब तक सबसे ज्यादा 12.1 फीसद वैक्सीन की डोज बर्बाद हुई है। इसके बाद हरियाणा का नंबर आता है, जहां अब तक 9.7 प्रतिशत डोज की बर्बादी हो चुकी है। पंजाब में 8.1 प्रतिशत, मणिपुर में आठ प्रतिशत और तेलंगाना में 7.5 प्रतिशत, जबकि राजस्थान में 5.5 प्रतिशत और बिहार में 4.9 प्रतिशत और मेघालय में 4.2 फीसद कोविड वैक्सीन बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं सबसे कम वैक्सीन बर्बाद करने वालों में अंडमान एवं निकोबार, दमन एवं दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल और मिजोरम शामिल हैं। अन्य राज्यों को इन राज्यों से सीख लेनी चाहिए।

कोविड के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम से जैव-विविधता और इसके संरक्षण की बढ़ी उम्मीद

भारत सरकार राष्ट्रीय जैव विविधता और मानव कल्याण मिशन के माध्यम से देश की समृद्ध जैव-विविधता और इसके संरक्षण को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत है ताकि वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं और जागरूक नागरिकों का इसपर ध्यान बना रहे।

इस कार्यक्रम के तहत लोगो में जैव-विविधता के बारे में जानकारी और विलुप्तप्राय जीवों की स्थिति के बारे में समय रहते पता लगाने पर जोर दिया जाएगा। संरक्षण की गतिविधियां सिर्फ संरक्षित क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लागू होने के बाद जैव-विविधता का विज्ञान अपनी दूसरी शाखाओं के मुकाबले मुख्य धारा में आ सकता है। इसके जरिए कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन के समय टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

जैव-विविधता वैसे तो हमारे जीवन को वृहत्तर तौर पर प्रभावित करती है पर आम-जन में इसकी चर्चा कम ही होती है। जब से कोरोना महामारी ने इंसानी समाज को अपने चपेट में लिया है सामान्य जन को जैव-विविधता का महत्व समझ में आने लगा है। इस समझ को और समृद्ध बनाने तथा जैव-विविधता की बारीकियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए 'राष्ट्रीय जैव-विविधता और मानव कल्याण मिशन' के नाम से एक योजना की शुरुआत हो रही है। इस मिशन का उद्देश्य संरक्षण को भारतीय मुख्य धारा में लाना है ताकि यह विषय वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं और जागरूक नागरिकों के बीच, इस पर निरंतर विचार-विमर्श चलती रहे।इस मिशन से संबंध रखने वाले संरक्षण जीवविज्ञानी और पर्यावरणविद् मानते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम से देश में संरक्षण की कोशिशों को बल मिलेगा और टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। उनका मानना है कि इस मिशन को महज संरक्षित क्षेत्र तक सीमित नहीं किया गया है बल्कि इसे आम जन तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी।

पीएम किसान योजना: क्या झारखंड के आदिवासी किसानों के साथ हो रहा है सौतेला व्यवहार?

मो. असगर खान

झारखंड में आदिवासियों की संख्या करीब 87 लाख है और कुल आबादी का करीब 26 प्रतिशत है। लेकिन प्रधानमंत्री सम्मान निधि कृषि योजना में लाभार्थी आदिवासी किसानों का प्रतिशत मात्र 12-13 प्रतिशत ही रहा है जो कि आबादी के लिहाज से काफी कम है।पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुकाबले झारखंड में इस योजना के लाभार्थियों का प्रतिशत काफी कम है। इन दो राज्यों के मुकाबले झारखंड में वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थी भी बहुत कम है। क्या इन दोनों मामलों में ऐसा कोई संबंध है? विशेषज्ञों की मानें तो वनाधिकार कानून का सही से न लागू होना एक वजह हो सकती है। पर इसके अतिरिक्त सरकारी महकमे की लापरवाही और भूमि को लेकर पिछले पांच सालों में हुए विवाद इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

झारखंड के खूंटी जिले के रहने वाले साठ वर्षीय समसोन तोपनो को जब खबर मिली की केंद्र सरकार अब किसानों को हर साल 6,000 रुपये देगी तो उन्हें लगा कि इस रकम से कुछ तो राहत मिलेगी। तोरपा ब्लॉक के बंसटोली गांव के रहने वाले तोपनो ने फटाफट आवेदन कर डाला। पर उन्हें आज तक इस प्रधानमंत्री सम्मान निधि कृषि योजना की एक भी किस्त नहीं मिली। तोपनो कहते हैं कि कोविड और लॉकडाउन ने तो रही-सही आमदनी भी खत्म कर दी। इसके पहले अनियमित बरसात और सूखे से परेशान थे। सवा दो एकड़ भूमि पर खेती कर जीवन-यापन करने वाले तोपनो के मुताबिक उनके क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सही नहीं है। इसलिए मानसूनी बारिश के भरोसे खेती होती है। बारिश हुई तो पैदावार होगी अन्यथा खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। इनके परिवार में पत्नी सहित पांच बच्चे भी हैं। तोपनो कहते हैं, ''जब पता चला कि प्रधानमंत्री सम्मान निधी कृषि योजना के तहत साल में 6,000 रूपये मिलेंगे तो राहत मिलने की उम्मीद जगी। मैंने उसी समय आवेदन कर दिया। आज तीन साल होने को हैं लेकिन एक पैसा नहीं मिला। पिछले साल दोबारा आवेदन किया। फिर भी एक पैसा अभी तक मेरे खाते में नहीं आया। ये पैसा मिलता तो कुछ खाद-पानी खरीदने में राहत मिल जाती। आमदनी घटती जा रही है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। मैंने किसान क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपये का कर्ज ले रखा है।

एक्टिविस्ट ग्लैडसन डुंगडुंग का कहना है, "आदिवासियों में इस योजना को लेकर भय भी है। जब पीएम किसान योजना शुरू हुई, तो ठीक उसी समय रघुवर दास (भाजपा सरकार) की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि योजना शुरू की थी। मुझसे कई ग्रामीण, किसानों ने तब इसे लेकर शिकायत की थी कि सरकारी लोग उनसे मुख्यमंत्री कृषि योजना का आवेदन भरवाने के क्रम में जमीन के सारे कागजात और सरकार को जरूरत पड़ने पर पांच एकड़ जमीन दिये जाने का डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरवा रहे थे। इससे लोगों में काफी डर बना।

अखिल भारतीय किसान सभा के झारखंड इकाई से जुड़े सदस्य भी देते हैं। झारखंड इकाई के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल लिंडा बताते हैं, ''पीएम किसान योजना के लिए राज्य के आदिवासी किसान रजिस्ट्रेशन तो कराते हैं लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता है। हम लोग रांची के नामकुम प्रखंड के दो गांव में गए थे। खरसीदाग में 30 आदिवासी किसानों ने 2019 में पंजीकरण कराया था, लेकिन सिर्फ तीन ही लोगों का पैसा आया। इसी तरह रुंगरुंग कोचा में 39 आदिवासी किसान ने पंजीकरण कराया, लेकिन पैसा सात लोगों का आया। वह भी 2019 के दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। सिर्फ दो बार। प्रफुल्ल लिंडा के मुताबिक जिन दो गांवों से 69 आदिवासी किसानों ने पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया था, उनमें से मात्र दस को ही एक या दो बार इस योजना के तहत मिलने वाली राशि मिल पाई। इनके अनुसार 59 किसानों को अब तक एक पैसे का भी लाभ नहीं मिला है। वर्ष 2018 में 1 दिसंबर को शुरू हुए इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत (जिनके पास पांच एकड़ तक खेत हो) किसानों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2,000 रुपये की तीन किश्तें दी जाती हैं। साल के 6,000 रुपये। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली यह राशि किसानों के खाते में सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आती है। अब तक आठ किश्तों की राशि दी जा चुकी है। आठवीं किश्त इसी महीने दी गयी है। हर चार महीने पर यह राशि दी जाती है। दिसंबर -मार्च, अप्रैल-जुलाई और अगस्त-नवंबर। हालांकि इस खबर में पिछली सात किस्तों के आंकड़े ही लिए गए हैं जो सरकारी वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

झारखंड में ऐसे आदिवासी किसानों की संख्या काफी अधिक है। पीएम किसान योजना की वेबसाइट के मुताबिक 22 अप्रैल 2021 तक देश के 11,77,40,373 किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इसमें झारखंड के 30,41,896 किसान हैं। राज्य के कुल लाभार्थी किसानों में आदिवासियों का प्रतिशत कम है। जबकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा में स्थिति काफी बेहतर है। इस पर झारखंड सरकार के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी का कहना है, ''जो आंकड़े आपने बताए हैं वही विभाग के पास भी है। यह गंभीर बात है। इसलिए इन आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद विभाग की ओर से आदिवासी किसानों के बीच पीएम किसान योजना के बारे में जागरूकता फैलाया जाएगा। जो भी किसान छूट गए हैं या छूट रहे हैं, उन्हें इस योजना से जोड़ने के लिए विभाग हर संभव प्रयास करेगा ताकि योजना के लाभ में आदिवासी किसानों का प्रतिशत बढ़े। झारखंड में आदिवासी समुदाय और उनकी निर्भरता को हम निम्न आंकड़ों से भी समझ सकते हैं।

झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के संस्थापक संजय बसु मल्लिक कहते हैं, झारखंड में आदिवासी समुदाय के 80 फीसदी लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं। आबादी के लिहाज से आदिवासी किसान का प्रतिशत बहुत ही कम है। मैं मानता हूं कि इसकी एक बड़ी वजह आदिवासियों के मुद्दे और उनके हित पर अधिकांश नौकरशाही का उदासीन रवैया रहा है। राज्य में वन अधिकार कानून और पेसा कानून को सही लागू नहीं करना हो या फिर पिछली सरकार (भाजपा) में पथलगड़ी का मुद्दा हो। आप इस संदर्भ में भी इसे देख सकते हैं कि नौकरशाहों का क्या रवैया रहा है।झारखंड में आदिवासी समुदाय में आज भी योजना को लेकर अज्ञानता है। उन्हें कहां, कैसे पता चलेगा कि प्रधानमंत्री क्या और कितना दे रहे हैं। प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है कि गांव-गांव जाकर इन मुद्दों के बारे में बताएं।

2011 के जनगणना को आधार मानते हुए अखिल भारतीय किसान सभा झारखंड इकाई का कहना है कि झारखंड में 31-32 लाख आदिवासी किसान परिवार हैं। सभा के मुताबिक झारखंड के किसान चार श्रेणी में आते हैं। 50 डिसमिल से कम वाले 17 प्रतिशत किसान है जो भूमिहीन कहलाते हैं। ढ़ाई एकड़ से कम वाले 33 प्रतिशत जो कि गरीब किसान हैं और पांच एकड़ से कम वाले 31 प्रतिशत जो कि सीमांती किसान और शेष धनी किसान के श्रेणी में आते हैं जिनके पास दस एकड़ से ज्यादा जमीन है। इनमें क्रमश 0-1, 39, 41 व 18 प्रतिशत आदिवासी किसानों की संख्या है। जबकि एक्टिविस्ट व लेखक ग्लैडसन डुंगडुंग और झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के संस्थापक संजय बसु मल्लिक मानते हैं कि आदिवासियों किसानों की संख्या इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। झारखंड में एक सच्चाई यह भी है कि सिंचाई की समस्याओं ने किसानों को कर्ज ओर से ढकेला है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 12.93 लाख किसान कर्ज के बोझ में डूबे हैं। राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि के लिए मात्र 13 प्रतिशत सिंचाई की ही सुविधा है जबकि 87 प्रतिशत भाग वर्षा पर आधारित है। ऐसे में यहां के कमजोर तबके के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत फायदा नहीं मिल पाना आश्चर्यचकित करता है।

झारखंड अलग राज्य बने 21 वर्ष हो गए।तकरीबन सभी दलों की सरकारें यहां रही। लेकिन आदिवासियों के मुद्दे पर सभी की गंभीरता वादों-घोषणाओं तक ही सीमित रही।

जलवायु परिवर्तन की चपेट में बिहार, बचाव नदारद

रोहित कुमार

आईआईटी के एक अध्ययन में सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन की चपेट से सबसे अधिक प्रभावित भारत के 50 जिले में बिहार के 14 जिले शामिल हैं।बिहार में प्रति हजार ग्रामीण आबादी पर वन क्षेत्र की कमी, अनाज उत्पादन में अनिश्चितता, खेती के लिए वर्षाजल पर निर्भरता और फसल-बीमा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का आभाव जैसे कई कारणों की वजह से बिहार जलवायु परिवर्तन की चपेट में है। इन खतरों के बावजूद बिहार के पास इससे निपटने के लिए कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं है। सरकार ने 2019 में इसे बनाने की कोशिश की थी पर सफलता नहीं मिली।

तमाम समस्याओं से जूझते बिहार के लिए एक और बुरी खबर! क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की मार भी राज्य पर सबसे अधिक पड़ने वाली है। यह खुलासा हुआ है इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) के एक अध्ययन से, जिसका मानना है कि भारत के 50 सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन की मार झेलने वाले जिलों में बिहार के 14 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं *अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, जमुई, शिवहर, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, लखीसराय, सिवान, सीतामढ़ी, खगड़िया, गोपालगंज, मधुबनी और बक्सर।* इस अध्ययन को आईआईटी मंडी और गुवाहाटी ने मिलकर किया है। इसके अनुसार बेंगलुरु देश का सबसे अधिक प्रभावित शहर होगा। इसके अतिरिक्त बिहार, झारखंड और असम के 60 फीसदी से अधिक जिले इसकी चपेट में आने वाले हैं।

इससे निपटने का कोई एक्शन प्लान न होने की स्थिति में बिहार के लिए जलवायु परिवर्तन की मार भारी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी) के द्वारा बिहार को लेकर तैयार ड्राफ्ट क्लाइमेंट एक्शन प्लान को भी बिहार सरकार ने हाल ही में लागू करने से इनकार कर दिया। डीएफआईडी, यूनाइटेड किंगडम की एक सरकारी एजेंसी है जिसे 2020 के बाद 'फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस' के नाम से जाना जाता है।बिहार पानी की समस्या से ग्रसित है। कहीं बाढ़ है तो कहीं भयंकर सूखा। दक्षिण बिहार हर साल बाढ़ की चपेट में आता है। वर्ष 2014 में नेशनल साइंसेज रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, राज्य का 21.1 प्रतिशत हिस्सा सिस्मिक जोन में आता है, जिसका मतलब यहां भूकंप का खतरा अधिक है। वहीं, यहां के 38 जिलों में से 27 जिले तेज हवा की वजह से परेशानी झेलते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से राज्य में बिगड़े मौसम का चरम देखने को मिलता है, चाहे वह बाढ़ हो, भूस्खलन हो या फिर सूखा हो।बीते दो दशक में देश के अन्य राज्यों के अलावा बिहार में भी जलवायु परिवर्तन की बहस तेज हुई है। हालांकि, नीति निर्माण में इसका प्रभाव न के बराबर है।

किन वजहों से जलवायु परिवर्तन की चपेट में बिहार ?

आईआईटी का अध्ययन कहता है कि बिहार में जंगलों का कम होना एक वजह है, खासकर ग्रामीण आबादी में। यहां कृषि उत्पादन भी एक समान नहीं होता। यहां किसी सीजन में ठीक उपज होती है तो कभी किसानों को औसत से भी कम उपज से संतोष करना होता है। अगर फसल खराब हुई तो नुकसान की भरपाई के लिए बीमा की भी पुख्ता व्यवस्था नहीं है। खेती-किसानी पर इसका प्रभाव है ही, इंसानों पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं के फिसड्डी होने से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिखने लगा है। यहां स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी बड़ी चिंता है।

लोगों की मासिक आमदनी को भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव झेलने के कारकों में शामिल किया गया है। कम आमदनी वाले लोग मौसम के प्रभाव से हुए नुकसान को झेलने में अधिक तकलीफ उठानी पड़ेगी। साथ ही, इंसान और पशुधन के संख्या अनुपात को भी ध्यान में रखा गया। मौसम की मार से आई तंगी को पशु बेचकर ठीक किया जा सकता है। इन मामलों में भी बिहार काफी पीछे है।

जलवायु परिवर्तन रोकने में कितना सक्षम जल-जीवन-हरियाली मिशन

बिहार सरकार ने दो अक्टूबर 2019 को जल-जीवन-हरियाली अभियान की शुरुआत की। इसका मकसद है जलवायु परिवर्तन की विभीषिका से निपटना। इसके लिए सरकार ने 25,524 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है।''राज्य सरकार का यह अभियान जलवायु परिवर्तन के नुकसान कम करने, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाने और पानी बचाने के उद्देश्य से शुरू हो रहा है,'' बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना शुरू करते समय कहा था। उन्होंने यूएन क्लाइमेंट चेंज राउंड टेबल 2020 में इस योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इससे पानी, जीवन और हरियाली में फर्क देखने को मिला है। इस मामले में जानकारों का कहना है कि बिहार की यह योजना जमीन पर ठीक से नहीं उतर पाई है।''इस योजना का मुख्य भाग पानी के संरक्षण पर ध्यान देता है, ताकि बिहार में पानी की किल्लत दूर की जा सके। इस अभियान में दूसके भी कई भाग हैं, लेकिन खुलकर कहें तो इसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुआ है,'' विज्ञान और तकनीक विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने कहा।उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य के पास टिकाऊ एक्शन प्लान नहीं है। अधिकारी मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन काफी गंभीर मुद्दा है। इसे जमीन पर लागू करना चुनौतीपूर्ण है। जानकार कहते आए हैं कि पूर्वी बिहार में बने बांध फायदे से अधिक नुकसान करते आ रहे हैं। लेकिन, यहां नौकरशाही ने अपने कान बंद कर लिए हैं। बाढ़ यहां के लिए व्यापार हो गया है। सब जानते हैं कि बाढ़ से नुकसान होगा, और फिर उसकी सरकार की ओर से भारपाई की जाएगी। समस्या को अभी भी पलटा जा सकता है। जैसे बाढ़ से हर साल उपजाऊ मिट्टी आती है। इलाके के किसानों को सशक्त कर उपजाऊ मिट्टी का लाभ उठाया जा सकता है।

वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यावरण के लिए एक विशेष यूनिट की घोषणा की थी। हालांकि, कोविड-19 आपदा की वजह से यह काम भी अटक गया।

हरियाली बचाने के वास्ते गोंड समुदाय ने शवों को नहीं जलाने का लिया फैसला

संख्या में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय गोंड ने हरियाली बचाने के उद्देश्य से शव के अंतिम संस्कार का तरीका बदलने का निर्णय लिया है। अब वे शव को जलाने के बजाए दफनाएंगे।

देश में हर साल शवों के अंतिम संस्कार के लिए 6 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं। इससे 80 लाख टन कार्बन डायऑक्साइड और पांच लाख टन राख पैदा होती है। राख अक्सर नदी में बहा दी जाती है। यद्यपि हिन्दू रीति रिवाज के मुताबिक शवों को लकड़ी के ढेर पर जलाया जाता है पर गोंड समुदाय में पहले शवों को दफनाया ही जाता था। इसे मिट्टी संस्कार के नाम से जाना जाता है। समय के साथ इस समुदाय ने भी शवों को जलाना शुरू कर दिया। शव जलाने में लकड़ी का उपयोग खत्म करने के लिए कुछ संस्थाएं बिजली चलित भट्ठी के उपयोग को प्रोत्साहित करने की मांग करती रही हैं।

देश के सबसे बड़े आदिवासी समाज के तौर पर गोंड समुदाय की पहचान होती है। हाल ही में इस समुदाय ने शवों के अंतिम संस्कार की अपनी वर्षों पुरानी परंपरा की तरफ लौटने का फैसला लिया। इस परंपरा में शवों को जलाने की बजाय दफनाया जाता है। इसे मिट्टी संस्कार का नाम दिया जाता है। महासम्मेलन में गोंड समुदाय के गणमान्य लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया। इस महासम्मेलन में गोंड समाज के करीब दो हजार प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

ढिबरा यानी माइका स्क्रैप पर निर्भर हैं लोग

झारखंड में अभ्रक का अवैध खनन जारी, होने वाले जान-माल के नुकसान का कोई लेखा-जोखा नहीं है।

वर्षों पहले झारखंड में अभ्रक खनन पर रोक लगा दी गयी थी। पर न तो अभ्रक के खानों पर कोई काम हुआ और न ही उससे प्रभावित लोगों का पुनर्वास। नतीजा यह कि अवैध रूप से अभ्रक खनन जारी है। कमजोर वर्ग अपने जीविकोपार्जन के लिए अभी भी ढिबरा यानी माइका स्क्रैप पर निर्भर है। इनके जान-माल के नुकसान का कोई हिसाब-किताब मौजूद नहीं है।

इन खदानों में काम करने वाली महिला और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर हो रहा है। खनन प्रभावित इलाकों में पर्यावरण पर पड़ते असर की बात तो खूब होती है पर एक बड़ी आबादी के बढ़ते कष्ट का जिक्र लगभग नहीं के बराबर होता है। खनन वाले इलाकों में काम करने वाले जानकारों ने पाया है कि ऐसे इलाकों में महिलाओं की तस्करी और उनके खिलाफ अपराध की घटनाएं अधिक होती हैं।

जंगल-जंगल घूम सकेंगे छत्तीसगढ़ के वन्यजीव, तैयार होगा वन गलियारा

दीपान्विता जी नियोगी

छत्तीसगढ़ में 121 वन्यजीव गलियारों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 14 गलियारों को विशेष तौर पर चुना गया है। ये गलियारे एक जंगल को दूसरे से जोड़ेंगे ताकि वन्यजीव आसानी से आवागमन कर सकें। इस काम को मुंबई स्थित एक गैर लाभकारी संस्थान की मदद से किया जा रहा है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद बाघ के अलावा दूसरे वन्यजीव भी निर्भिक होकर जंगल-जंगल घूम सकेंगे। कई गलियारों के रास्ते में विकास की परियोजनाएं जैसे सड़क और खदान बन गए हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ऐसे क्षेत्र में काम किया जाएगा और जंगलों को पुनः जोड़ा जाएगा।

जानकार मानते हैं कि दो जंगलों के बीच कॉरीडोर या गलियारा दुरुस्त होने से बड़े इलाके में रहने वाले जीवों का बेहतर संरक्षण हो सकेगा। वाइल्डलाइफ कॉरीडोर यानी दो बड़े जंगलों को जोड़ने वाला एक ऐसा वन गलियारा जिससे होकर जानवर आसानी से एक से दूसरे जंगल में जा सकें। इस गलियारे में जंगल जैसा माहौल होता है और इंसानी गतिविधि भी नहीं होती जिससे जानवर बेखौफ होकर घूम सकते हैं। ये गलियारे प्राकृतिक रूप से बने होते हैं लेकिन वर्तमान विकास के मॉडल की वजह से इनका स्वरूप बिगड़ा है और वन्यजीवों की मुश्किलें बढ़ी हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने इन गलियारों के संरक्षण, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक योजना बनाई है। इसके लिए कैंपा (कंपन्सेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑथोरिटी) प्रदेश में ऐसे कॉरिडोर को चिन्हित कर रही है। इस प्रोजेक्ट को दो बड़ी प्रजाति के जीव, हाथी और बाघ को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। ये जीव अक्सर इन गलियारों का इस्तेमाल कर खाने और नए इलाके की तलाश में जंगल-जंगल भटकते रहते हैं। इनके अलावा, तेंदुए, स्लॉथ बियर और जंगली भैंसें भी इसका इस्तेमाल करते हैं।

अबतक 121 कॉरीडोर को चिन्हित किया गया है जिसे वन विभाग विकसित करेगा। इसमें से 14 गलियारों को प्रमुखता दी गई है और इसके निर्माण को विभाग अधिक तवज्जों देगा।

वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (डब्लूआईआई) भी गलियारों को

विकसित करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट इनसे इतर है।

छत्तीसगढ़ कैंपा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास राव ने मोंगाबे-हिन्दी को बताया कि देहरादून स्थित डब्लूआईआई ने कुछ वक्त पहले इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन इसमें कॉरीडोर का प्रबंधन और संरक्षण शामिल नहीं था। इसले अलावा, उनके प्रोजेक्ट में गलियारा सिर्फ बाघों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है।

छत्तीसगढ़ की योजना देश में अपने आप में नई है। देश में कई जंगल हैं जो अलग-थलग हैं। इसके मूल में हैं खनन, सड़क परियोजनाएं इत्यादि। हमारी इस मुहीम में हम ऐसे अलग-थलग पड़े जंगलों को आपस में जोड़ेंगे। कैंपा में इस तरह के काम का प्रावधान है। हमने 2020-21 के ऑपरेशनल प्लान में इस योजना को शामिल किया है। इस समय हम जमीन पर योजना को उतारने की तैयारी कर रहे हैं,'' उन्होंने कहा। बिलासपुर के कोटा रेंज में वन का सर्वे किया। यह इलाका वन गलियारा में शामिल है। राव ने बताया कि मुंबई स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था के निदेशक शिवराज चवन ने राज्य को इस प्रोजेक्ट का खांचा तैयार करने में मदद किया। छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण जंगल गलियारा कान्हा-अचानकमार कॉरीडोर है।''हम विकास चाहते हैं, लेकिन साथ में अपना मूल भी बचाना चाहते हैं। इस समय एक टाइगर रिजर्व से दूसरे के बीच आने-जाने की सुविधा नहीं है। वन विभाग राज्यभर में जंगलों को एक दूसरे से जोड़ना चाहती है। अगर भारत सरकार अनुमति देती है तो हम ओडिशा और झारखंड के जंगलों से भी छत्तीसगढ़ के जंगलों को जोड़ेंगे। इन राज्यों से हाथी छत्तीसगढ़ में आते हैं।

फिलहाल सिर्फ राज्य के भीतर ही जंगलों को जोड़ा जाएगा,'' उन्होंने कहा। पहली प्राथमिकता अचानकमार टाइगर रिजर्व और भोरमदेव वाइल्डलाइफ सेंचुरी को जोड़ने की होगी। ये जंगल मुंगेली और कबीरधाम जिले में हैं। इसके बाद मध्यप्रदेश के कान्हा और छत्तीसगढ़ के भोरमदेव के बीच के प्राकृतिक कॉरीडोर को विकसित किया जाएगा। इस काम के लिए पहले चरण का बजट 20 करोड़ रुपए रखा गया है।

अवैध बालू खनन बना झारखंड की नदियों के लिये काल

रांची : झारखंड में अवैध बालू खनन का धंधा बहुत पुराना है। इस पर आज तक कितना भी शोर हुआ पर झारखंड में नदियों से अवैध बालू का खनन आज तक अनवरत जारी है। लॉकडाउन में तो इसमें और तेजी आयी है। राज्य में एक बार मुबंई की कंपनी को बालू खनन का ठेका मिला था। उस वक्त भी इस पर बवाल हुआ था।

बालू के अवैध उठाव को लेकर लगातार चिंता जतायी जाती रही है. सड़क से सदन तक इस पर बवाल होता रहा है। बावजूद इसके बालू को लगातार हमेशा से विवाद और सियासत होता रहा है। पर जमीनी तौर पर स्थिति और भी भयावह दिखती है।लोगों को घर बैठे बालू की सुविधा मिले, इसके लिये सैंड टैक्सी के कॉन्सेप्ट पर राज्य सरकार काम कर रही है. उम्मीद की जा रही है कि वाजिब कीमत पर नागरिकों के दरवाजे तक बालू पहुंचाया जायेगा। इधर, बालू का अवैध उठाव और अवैध तरीके से परिवहन का सिलसिला अब भी जारी है। जेसीबी तक से बालू उठाव हो रहा है। इससे ना सिर्फ नदियों की गोद भयावह तरीके से सूनी हो रही है। नदियां अपने रास्तों से भटकने लगी हैं .बालू के माइनिंग के संबंध में सैंड माइनिंग गाइडलाइन 2020 (केंद्र सरकार), एनजीटी के साथ-साथ राज्य सरकार के अपने प्रावधान हैं। एनजीटी की मानें तो जून से अक्टूबर के बीच बालू के उत्खनन पर रोक रहती है।किसी भी स्थिति में जेसीबी से बालू का उठाव नहीं करना है। पर राजधानी रांची से लेकर दुमका तक नदियों से बड़ी-बड़ी मशीनों (जेसीबी) से बालू का उत्खनन किया जाना आम दृश्य है।

दिलचस्प तो यह कि दिन के उजाले में ही नदी से जेसीबी से बालू का उठाव होता है। जेसीबी के अलावे हाइवा, ट्रैक्टर और अन्य छोटे मालवाहक गाडियों से भी बालू का अवैध उठाव हो रहा है। उठाव का ये सिलसिला खासकर दिसंबर से मई-जून तक जारी रहता है। बारिश के मौसम से पहले टारगेटेड जगहों पर बालू का स्टॉक जमा किया जाता है। और दुगुने तिगुने कीमत पर इसे बेचा जाता है।

तीसरे लहर से निबटने में जुटी झारखंड सरकार

कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर की संभावना के मद्देनजर तैयारी में जुटी राज्य सरकार, वेबिनार आयोजित कर देश एवं राज्य के विभिन्न अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टर एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ मुख्यमंत्री ने किया विचार-विमर्श।

कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर की तैयारी में विशेषज्ञ डॉक्टरों के सुझाव महत्वपूर्ण

मुख्यमंत्री

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय से वेबिनार के जरिए देश एवं राज्य के विभिन्न अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ संवाद किया। कोरोना संक्रमण से निपटने तथा मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर विशेषज्ञ डॉक्टरों के सुझाव और अनुभवों के बारे में जाना। सभी डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमण जैसे खतरनाक महामारी से निपटने के दौरान स्वयं द्वारा किए गए कार्यों एवं अनुभवों को मुख्यमंत्री के साथ साझा किया तथा कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर आने वाली मुश्किलों और चुनौतियों के संबंध में विचार-विमर्श किया तथा चुनौतियों से निपटने की तैयारी कैसी होनी चाहिए इस संबंध में अपने सुझाव भी दिए।

सभी स्वास्थ्य संसाधनों को पहले ही चुस्त-दुरुस्त करना जरूरी

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर की संभावनाओं को देखते हुए आप सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों का सुझाव लेना बहुत ही आवश्यक है। आप सभी के अनुभव, सहयोग और सुझाव से संक्रमण के पहले लहर से राज्य सरकार ने निपटने का काम किया था परंतु अचानक संक्रमण की दूसरी लहर और खतरनाक रूप से हम सभी के बीच आ खड़ी हुई। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की माने तो कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर आने की भी संभावना है। तीसरा लहर ज्यादा आक्रमक न हो, इसके लिए जरूरी है कि पहले से ही तमाम स्वास्थ्य संसाधनों को चुस्त-दुरुस्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे लहर की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए राज्य के सभी जिला एवं प्रखंड स्तर के अस्पतालों में अलग से शिशु वार्ड तैयार करने का निर्देश राज्य सरकार ने दिया है। सभी अस्पतालों में चिल्ड्रेन केयर यूनिट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

राज्य सरकार सामाजिक जागरूकता के साथ आगे बढ़ रही है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड प्रदेश पारंपारिक रहन-सहन एवं ट्रेडिशनल कल्चर के लिए जाना जाता है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में कोरोना संक्रमण के उपचार एवं वैक्सीनेशन को लेकर तमाम भ्रातियां हैं। राज्य सरकार सामाजिक जागरूकता के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा झारखंड के अंदर 24 जिले हैं जिसमें 23 जिले अलग-अलग राज्यों के बॉर्डर क्षेत्र से जुड़े हैं। राज्य सरकार ने इंटर स्टेट मूवमेंट को रोकने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निरंतर प्रयास से राज्य में पॉजिटिव केसों की संख्या में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने मृत्यु के आंकड़ों को किसी भी प्रकार से छिपाने का कार्य नहीं किया है बल्कि सही-सही आंकड़े प्रेषित किए हैं ताकि हमारा राज्य सही दिशा की ओर आगे बढ़ सके। राज्य सरकार का प्रयास है कि कोरोना संक्रमण से किस तरह निपटें की स्थिति नियंत्रण में हो सके, यही कारण है कि आप सभी विशेषज्ञों के साथ वेबिनार का आयोजन आज किया गया है ताकि तीसरी लहर आने से पहले आप लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव और सहयोग से हम अपनी कार्य योजना तैयार कर सकें।

इन विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने प्रजेंटेशन के माध्यम अपने सुझाव और अनुभव साझा किया

वेबिनार के जरिए Dr.Roderico WR India, Dr. Ashok Deorari, HOD Pediatrics, AIIMS, Dr. Neelam Mohan, Director of Pediatrics Medanta New Delhi, Dr.Pradeep, Epidemiology NIMHAS ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के समक्ष अपने सुझाव एवं अनुभव साझा किए। सभी विशेषज्ञों ने कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर से बच्चों के बचाव एवं बेहतर उपचार से संबंधित जानकारियां रखी। मुख्यमंत्री ने इन सभी डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके सुझाव और अनुभव कोरोना संक्रमण से निपटने में महत्वपूर्ण हैं। आपके सुझाव के अनुरुप ही राज्य सरकार आगे की तैयारी और कार्य योजना बनाएगी। इस अवसर पर शिशु रोग विशेषज्ञ रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल रांची के डॉक्टर राजेश ने धन्यवाद संबोधन दिया। रिम्स एवं अन्य अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टर एवं शिशु रोग विशेषज्ञ इस वेबिनार में उपस्थित थे।

वेबिनार में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, नगर विकास सचिव श्री विनय कुमार चौबे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बना झारखंड

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में द्रुत गति से बढ़े संक्रमित मरीजों की जीवन रक्षा के लिए समय रहते ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया। अपने सीमित संसाधनों के साथ इस कार्य में काफी हद तक सरकार सफल भी रही। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने दो दिन पूर्व ही रामगढ़ के मांडू स्थित डीएवी स्कूल, घाटोटांड़ में ऑक्सीजन युक्त 80 बेड के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जरूरतमंदों को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार सभी जिलों में ऑक्सीजन बैंक बनाने और जिलों के सदर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की दिशा में भी काम शुरू कर चुकी है। ऑक्सीजन की उपलब्धता के मामले में राज्य अब आत्मनिर्भर हो गया है।

दूसरी लहर ज्यादा चिंताजनक

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक रही। नेशनल क्लीनिकल रजिस्ट्री के अनुसार पहली लहर में लोगों में सांस की तकलीफ 41.7 प्रतिशत थी, जो दूसरी लहर में बढ़कर 47.5 प्रतिशत हो गई। यह एक चिंताजनक स्थिति रही। सांस की तकलीफ बढ़ने पर मेडिकल ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ने लगी। मुख्यमंत्री हालात पर लगातार नजर बनाए रखे । राज्य के विशेषज्ञों की भी राय रही कि जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए राज्य को ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना होगा।

ऑक्सीजन टास्क फोर्स का गठन

संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए ऑक्सीजन टास्क फोर्स का गठन किया गया। टास्क फोर्स द्वारा राज्य में ऑक्सीजन का उत्पादन कैसे बढ़े, ऑक्सीजन सिलेंडर व जरूरी उपकरणों की उपलब्धता और अस्पतालों तक निर्बाध आपूर्ति कैसे हो, इस पर योजना बनाकर काम किया गया। अप्रैल 2021 तक राज्य में 12 ऑक्सीजन रि-फिलिंग यूनिट थी। ये यूनिट प्रतिदिन 6000 से 7000 सिलेंडर को रिफिल करने की क्षमता रखती थी। राज्य में कार्यरत पांच ऑक्सीजन निर्माताओं द्वारा 315 टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा था। 22 अप्रैल तक इस क्षमता को बढ़ाकर 570 टन प्रतिदिन किया गया। इसके बाद भी राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता को और बढ़ाने का काम जारी रहा। परिणाम यह रहा कि झारखंड अब दिल्ली, उत्तरप्रदेश समेत अन्य राज्यों को पहले से अधिक ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है।

22 अप्रैल 2021 तक राज्य में 80 से 100 टन ऑक्सीजन रोजाना की मांग थी, जबकि राज्य में उत्पादन उससे कहीं ज्यादा हो रहा था। लेकिन, ऑक्सीजन सिलेंडर और संबंधित उपकरणों की कमी की वजह से शुरू में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में कुछ दिक्कत हुई। इसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता के लिए प्रयास किए गए। राज्य में उपलब्ध इंडस्ट्रियल सिलेंडरों को भी मेडिकल सिलेंडरों के रूप में परिवर्तित किया गया।जिससे बहुत मदद मिली।

किसानों के तरबूज की मिलेगी उचित कीमत?

संवाददाता

रांची : झारखंड के कई जिलों से शिकायतें लगातार आ रही थी कि, किसानों के खेत में तरबूज बर्बाद हो रहे हैं। इसे लेकर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी को राज्य के संबंधित डीएचओ और बाजार समिति के सचिव के साथ समन्वय स्थापित कर किसानों को राहत देने के लिए कहा । विभागीय सचिव के द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार और उद्यान विभाग के निदेशक ,भेजफेड के एमडी सहित सम्बंधित डी एच ओ एवं बाजार समिति के सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। जहां विभागीय सचिव ने सभी को निर्देश दिया है कि वे अभिलंब किसानों के खेतों में पड़े तरबूज की खपत कैसे की जाए उसे लेकर जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करें।

जूस बनाने वाली कंपनी से बात की जा रही है जो खूंटी के किसानों के तरबूज को लेगी
वरुण रंजन
निदेशक,उद्यान विभाग

उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर जिन जिलों में तरबूज की खेती नहीं हो रही है उन जिलों से जहां तरबूज की खेती ज्यादा हो रही है तरबूज भेजे जाए । राज्य के बाहर कोलकाता ,उड़ीसा, बिहार एवं दिल्ली से भी समन्वय स्थापित किए जाएं, बाजार समिति के सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने जिले में किसानों के द्वारा तरबूज की कितनी पैदावार की जा रही है और खपत की स्थिति क्या है इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और तुरंत में वहां के खरीददारों के साथ बैठक कर किसानों के तरबूज उचित कीमतों पर कैसे लिया जाए इसे देखें। जिला उद्यान पदाधिकारी एवं बाजार समिति के सचिव ने विभाग के सचिव को जानकारी देते हुए बताया की लॉक डाउन की वजह से खरीददार किसानों को उचित कीमत देने के लिए तैयार नहीं है, विभागीय सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि वह किसान को अपना मेहनतआना मिल सके उन्हें नुकसान ना हो यह सुनिश्चित करने का काम करें। उनके इसी कार्य कुशलता के आधार पर आने वाले समय में राज्य सरकार उन्हें सम्मानित करने का भी काम करेगी।

कृषि विभाग के सचिव ने भेजफेड के एम डी को कहा कि इस कोरोना महामारी में भेजफेड को ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, उन्होंने निर्देश दिया है कि राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर तरबूज की खरीददारी कर घरों तक पहुंचाने का भी काम करें, जिससे किसानों को राहत दिया जा सके। भेजफेड को विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए है। बाजार समिति की सचिव को प्रत्येक दिन के रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के विशेष सचिव प्रदीप हजारे को न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने को लेकर जल्द बैठक कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। वही सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार श्री मृत्युंजय वर्णवाल ने कहा कि वर्तमान में जो कोल्ड स्टोरेज हैं उसे और मजबूत करने की आवश्यकता है, वही विभिन्न राज्यों से समन्वय स्थापित करने की भी बातें उन्होंने कही। उद्यान विभाग के निदेशक वरुण रंजन ने कहा की जूस बनाने वाली कंपनी से बात की जा रही है जो खूंटी के किसानों के तरबूज को लेगी, बिहार बंगाल और उड़ीसा से समन्वय स्थापित किए जा रहे हैं । उन्होंने विभागीय सचिव से आग्रह किया की विभिन्न जगहों पर किसानों के तरबूज के पैदावार होते हैं, खरीददार को किसी एक पॉइंट को बनाकर वहां से तरबूज दिए जाए, जिससे राज्य के बाहर आसानी से तरबूज भेजे जा सके। विभागीय सचिव ने इसे भी सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं।

महर्षि सेवा संस्थान ने लोगों को किया जागरूक

रांची : 23 मई 2021 को महर्षि सेवा संस्थान की ओर से फिरायालाल चौक पर corona का भयावह चित्र बनाया गया जिससे लोगों को यह पता चल सके कि आज कोरोना कितनी गंभीर स्थिति में आ चुका है। लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसने एक विकराल राक्षस का रूप धारण कर लिया है।संस्थान के अध्यक्ष जितेंद्र जी ने लोगों से आग्रह किया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन करें । घर पर रहे और सुरक्षित रहे, घर पर रहकर वे अपने साथ-साथ दूसरों के जान की भी रक्षा कर सकते है। साथ ही लोगों को "टीका लगाये, सुरक्षित रहें" का संदेश भी दिया।जागरूकता अभियान का यह पहला दिन था जिसके अंतर्गत यह काम शुरू किया गया है आने वाले दिनों मे मोराबदी, बिरसा चौक, कचहरी चौक , बूटी मोड में भी इस कोरोना के चित्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम निरंतर जारी रहेगा।

चित्रकारी के कार्य संस्थान के सचिव के सचिव सुनील जी के द्वारा किया गया जिसमें गौरव और सौरव का सहयोग रहा। यह जानकारी राजीव गुप्ता ने ग्रीन रिवोल्ट को दी।

खाद की कालाबाजारी में लैम्प्स पैक्स से भी कमिशन की मांग

रांची संवाददाता :धान रोपा का समय आ रहा है और अभी से ही झारखंड में खाद की कालाबाजारी, कीमत बढाने से लेकर कमीशन का खेल शुरू हो गया है। कृषि मंत्री बादल ने माना है कि यह समस्या राज्य में फिर से सामने आयी है.उन्होंने कालाबाजारी को रोकने को तत्काल एक टीम का गठन कर छापामारी करने को कहा है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अलाना उन्होंने विभागीय सचिव अबु बकर सिद्दीकी को भी एक्शन लेने को कहा है। अब सचिव सभी जिलों के डीसी से बात कर ऐसे मामलों की रोकथाम, जांच और लीगल एक्शन लेने को टास्क फोर्स बनाने को कहेंगे।

बादल के अनुसार किसानों को बढी हुई कीमतों पर खाद मिलने की शिकायत मिल रही है। पिछले साल भी कई जिलों में ऐसी शिकायतें मिली थीं जिसे ग्रीन रिवोल्ट ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद खाद की कालाबाजारी करने वालो पर कार्रवाई की गयी थी। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान किसान खुद परेशान हैं। उनके लिए खेती ही उनके जीविकोपार्जन का माध्यम है। ऐसे में कालाबाजारी की शिकायत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं राज्य के कई लैम्प्स और पैक्स के अध्यक्षों ने शिकायत की है कि उनके 8 प्रतिशत तक कमीशन मांगा जा रहा है। मंत्री बादल ने इस मामले पर भी संज्ञान लिया है।

राज्य सरकार के प्रयासों से मिल रहा झारखंड की जैव विविधता को बढ़ावा

अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई

- **झारखंड के वन क्षेत्र में वन्य प्राणियों के साथ विभिन्न प्रजातियों के पेड़ और औषधीय पौधों की है भरमार।**
- **संरक्षण और पौधरोपण से लगातार हो रही है वन क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी।**

मनोरंजन सिंह

झारखंड को प्रकृति ने खुलकर अपने वरदान से नवाजा है। राज्य की पहचान यहां के वन क्षेत्र और उसकी जैव विविधता है। सरकार के प्रयासों से राज्य के वन क्षेत्रों में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही यहां की जैव विविधता में भी इजाफा हो रहा है।

वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध :सरकार वनों के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के सतत प्रयासों से राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33 .81 प्रतिशत हिस्से में वन है। यह राष्ट्रीय वन नीति 1988 के आलोक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के 30 दिसंबर 2019 के प्रतिवेदन में बताया गया है कि राज्य के वन क्षेत्रों में 58 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार लगातार वन भूमि पर पौधरोपण को बढ़ावा दे रही है। साथ ही सभी जिलों में नदियों के किनारे पौधरोपण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे भी वन क्षेत्र में वृद्धि हो रही है।

झारखंड में जैव विविधता की विशेषताएं :झारखंड की जैव विविधता यहां की विशिष्ट भौगोलिक बनावट और जलवायु की देन है। यहां नेतरहाट का पहाड़ी क्षेत्र है, जो समुद्र तल से करीब 3622 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े साल के जंगलों वाला इलाका माना जाता है।इसके अलावा पलामू, रांची, खूंटी सहित अन्य जिलों में भी सघन जंगल है। इन जंगलों में हाथी, सांभर, चीतल, तेंदुए, बंदर, लंगूर और भेड़िए जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। इन जंगलों में सरीसृप व कीटों की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। पलामू में अभी भी बाघ मिलते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व में उनके संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। दलमा में बड़ी संख्या में हाथी पाए जाते हैं। मुटा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। यहां इनके प्रजनन और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह महुआडाड़ में भेड़िया अभयारण्य बनाया गया है। उधवा जल पक्षीय शरण स्थली में तरह-तरह के पक्षी देखे जा सकते हैं।

गौरतलब है कि राज्य के जंगलों में साल, सागवान, पलाश शीशम, सागवान जैसे पेड़ों से लेकर केंद, बांस व तरह-तरह की झाड़ियां मिलती हैं। वहीं इन जंगलों में कई तरह के औषधीय पौधे भी पाये जाते हैं। ये सब जैव विविधता को समृद्धि प्रदान करते हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस विशिष्ट जैव विविधता को संरक्षित और संवर्धित कर झारखंड की पहचान को और ऊंचाई दी जाये

भारतीय नौसेना ने डिजाईन किया ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम

ललित मौर्य

इस ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम की मदद से शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर छोड़ी गई ऑक्सीजन को फ़िल्टर करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है

आज देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है जिसके कारण देश में ऑक्सीजन का गंभीर संकट बना हुआ है इसी संकट को देखते हुए नौसेना की दक्षिणी कमान के डाइविंग स्कूल ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए एक नया 'ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम' (ओआरएस) डिजाइन किया है।

गौरतलब है कि डाइविंग स्कूल के पास इस क्षेत्र में काफी विशेषज्ञता है क्योंकि स्कूल द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ डाइविंग सेट्स में इस आधारभूत सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इससे पहले 6 मार्च 2021 को केवड़िया में संयुक्त कमांडरों के हुए एक सम्मेलन में सेना न माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष इसी आईडिया पर आधारित एक छोटे मॉडल का प्रदर्शन किया था। यह ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम (ओआरएस) मौजूदा ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवनकाल को दो से चार बार तक बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है आमतौर पर एक मरीज जितनी ऑक्सीजन लेता है उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही फेफड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जबकि बाकी हिस्सा शरीर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वातावरण में बाहर छोड़ दिया जाता है। इस छोड़ी गई ऑक्सीजन का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते इसमें से कार्बन डाई ऑक्साइड को हटा दिया जाए। ऐसा करने के लिए इस सिस्टम में रोगी के मौजूदा ऑक्सीजन मास्क के साथ एक दूसरा पाइप जोड़ा जाता है जो कम दबाव वाली मोटर का उपयोग करके रोगी द्वारा निकाली गए ऑक्सीजन को अलग करता है। इस ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम (ओआरएस) को

डाइविंग स्कूल के लेफ्टिनेंट कमांडर मयंक शर्मा ने डिजाइन किया है।

कैसे काम करता है यह पूरा सिस्टम

मास्क का इनलेट पाइप (ऑक्सीजन के लिए) एवं मास्क का आउटलेट पाइप (बाहर निकाली हवा के लिए) प्रयोग होता है हर समय गैसों का उचित दबाव एवं एक-दिशा में प्रवाह बना रहे इसलिए इन दोनों ही पाइप्स को एक नॉन रिटर्न वाल्व के साथ फिट किया जाता है इस-ाकी मदद से रोगी में डाईल्यूशन हाईपोक्सिया की स्थिति नहीं पैदा होती है। निकाली गई गैसों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, को इसके बाद एक बैक्टीरियल वायरल फिल्टर एंड हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज फ़िल्टर में डाला जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की वायरसजनित अशुद्धियां दूर की जा सकें। इस वायरल फिल्ट्रेशन के बाद यह गैसें एकहाइ ग्रेड कार्बन डाई ऑक्साइड स्क्रबर से एक हाइ एफिशिएंसी पर्टीक्युलेट (एचईपीए) फ़िल्टर में से होकर गुजरती हैं ये फिलटर कार्बन डाई ऑक्साइड एवं अन्य कणों को अवशोषित करके शुद्ध ऑक्सीजन को प्रवाहित होने देता है। इसके बाद स्क्रबर की मदद से यह ऑक्सीजन वापस रोगी के फेस मास्क से जुड़े श्वसन पाइप में डाली जाती है, जो ऑक्सीजन की प्रवाह गति में बढ़ोतरी कर देती है साथ ही इससे सिलिडर से आने वाली ऑक्सीजन के इस्तेमाल में भी कमी आ जाती है।

इस ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम में हवा के प्रवाह को कार्बन डाई ऑक्साइड स्क्रबर के आगे फिट किए गए मेडिकल ग्रेड पंप की मदद से बनाए रखा जाता है, जो सकारात्मक प्रवाह सुनिश्चित करता है, इससे रोगी को आरामदायक ढंग से सांस लेने में सुविधा होती है। वहीं डिजिटल फ्लो मीटर ऑक्सीजन की प्रवाह दर की निगरानी करते रहते हैं साथ ही इसमें में स्वचालित कट-ऑफ के साथ इनलाइन ऑक्सीजन और कार्बन डाई ऑक्साइड सेंसर भी लगे होते हैं, जो ऑक्सीजन का स्तर सामान्य से घटने या कार्बन डाई ऑक्साइड का स्तर बढ़ने पर ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम (ओआरएस) को अपने आप बंद कर देते हैं। हालांकि इस कट-ऑफ से सिलेंडर से आ रही ऑक्सीजन का सामान्य प्रवाह प्रभावित नहीं होता है, ऐसे में यदि कट-ऑफ या अन्य कारणों ओआरएस बंद भी हो जाए तब भी रोगी आसानी से सांस लेता रह सकता है।

इस ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम का पहला पूरी तरह से कार्यशील प्रोटोटाइप 22 अप्रैल 2021 को बनाया गया थो जिसके बाद विशेषज्ञों ने इसका परिक्षण किया था जिसमें कुछ संशोधनों के सुझाव के साथ इस डिजाइन को पूरी तरह संगत पाया गया थो गौरतलब है कि नीति आयोग के निर्देशों पर तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (एससीटीआईएमएसटी) के विशेषज्ञों की टीम ने इस प्रणाली का विस्तृत विश्लेषण एवं आकलन किया था। 18 मई 2021 को एससीटीआईएमएसटी के निदेशक द्वारा इस ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम (ओआरएस) को एक प्रारंभिक मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्रदान दे दिया गया था। अब मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार क्लीनिकल परीक्षणों के लिए इस प्रणाली को आगे बढ़ाया गया है, जिसके शीघ्र पूरा होने की उम्मीद है, इसके बाद यह डिजाइन देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा। खास बात यह है कि इस ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम में उपयोग की जाने वाले सभी सामग्री देश में स्वदेशी और स्वतंत्र तौर पर उपलब्ध हैं, ऐसे में हमें इसके लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।

ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम प्रोटोटाइप की लागत काफी कम है ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण से हर दिन होने वाली करीब 3,000 रुपये की अनुमानित बचत के कारण यह घटकर 10,000 रुपये रह गई है।

इतिहास का नौवां सबसे गर्म रहा 2021 का अप्रैल

इतिहास का नौवां सबसे गर्म अप्रैल, 2021 में रिकॉर्ड किया गया है एनओएए के नेशनल सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल इंफॉर्मेशन (एनसीईआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 में तापमान 20वीं सदी के औसत से 0.79 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। गौरतलब है कि 20वीं सदी का औसत तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि इसके बावजूद अप्रैल 2021 में तापमान 2013 के बाद से सबसे कम रिकॉर्ड किया गया थो इसके लिए पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ला नीना की घटना को जिम्मेवार माना जा रहा है यही नहीं यूरोपियन कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार इस वर्ष 2003 के बाद से यूरोप में अप्रैल का तापमान सबसे कम थो रिकॉर्ड के मुताबिक जहां 2016 में अप्रैल महीन का तापमान सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था, जो औसत से 1.12 डिग्री सेल्सियस ज्यादा थो इससे पहले दिसंबर 1984 में अप्रैल का तापमान औसत से नीचे पाया गया था उसके बाद से तापमान में वृद्धि ही दर्ज की गई है

एनओएए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 का तापमान 20वीं सदी के औसत से 0.79 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था

आंकड़ों के अनुसार दुनिया के अधिकांश हिस्सों में तापमान औसत से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है वहीं पूर्वी कनाडा, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी एशिया में तापमान औसत से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है वहीं दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका, मध्य यूरोप, मध्य एशिया के कुछ हिस्सों, ऑस्ट्रेलिया, मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागरों के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक ठंडा तापमान रिकॉर्ड किया गया है

संरा की रिपोर्ट:धरती का 17 फीसदी हिस्सा है संरक्षित

धरती की लगभग 16.6 फीसदी जमीन अब संरक्षित क्षेत्रों के रूप में हैं, इस बात की जानकारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई रिपोर्ट प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2020 में सामने आई है वहीं यदि इस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यह 2.25 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है रिपोर्ट के अनुसार यदि इस क्षेत्र में 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को और जोड़ दिया जाए तो हम आइची जैव विविधता लक्ष्य-11 को पूरी तरह से हासिल कर लेंगें

पिछले दशक की शुरुवात से देखें तो इन संरक्षित क्षेत्रों में करीब 42 फीसदी की वृद्धि हुई है यदि आकार के दृष्टिकोण से देखें तो यह 2010 के बाद से भारत के आकार का करीब सात गुना हो गया है इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) द्वारा 19 मई को जारी किया गया था।

वहीं 2010 के बाद से समुद्रों का संरक्षित क्षेत्र तीन गुना से अधिक हो गया है, इसके बावजूद वो समुद्रों का केवल 8 फीसदी हिस्सा ही है, जो अभी भी आइची जैव विविधता लक्ष्य-11 में निर्धारित 10 फीसदी के लक्ष्य से पीछे है यह क्षेत्र अब बढ़कर लगभग 2.81 करोड़ वर्ग किलोमीटर हो चुका है। हालांकि यदि आंकड़ों के देखें तो हमने स्थलीय इलाकों को संरक्षित क्षेत्र में बदलने के लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है साथ ही समुद्री क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के हम करीब ही हैं, पर क्या केवल इन क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना ही काफी है इन क्षेत्रों में से कितने क्षेत्रों में वास्तविक रूप से जैवविविधता को संरक्षित किया जा रहा है यह कहीं ज्यादा मायने रखता है रिपोर्ट से पता चला है कि कुछ संरक्षित क्षेत्र दूसरों क ी

तुलना में जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र को बचाने का काम कहीं बेहतर तरीके से कर रहे हैं

सुरक्षा के नाम पर केवल बाड़ लगा देना ही काफी नहीं। यूनेप की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन के अनुसार जो लक्ष्य हासिल किया है वो प्रभावित करने वाला है इसके लिए देश बधाई के पात्र हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है उनके अनुसार केवल सुरक्षा के नाम पर बाड़ लगा देना ही काफी नहीं है हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वहां संरक्षण तय मानकों के अनुसार ही हों

उनके अनुसार यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यह जमीन द्वारा अवशोषित किए जाने वाले कार्बन के कुल हिस्से का करीब पांचवा भाग सोख लेते हैं हालांकि संरक्षित क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है इसके बावजूद दुनियाभर में जैवविविधता में तेजी से गिरावट आ रही है संयुक्त राष्ट्र की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार करीब 10 लाख प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में किए एक शोध से पता चला है कि 1960 से 2019 के बीच करीब 4.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के भूमि उपयोग में बदलाव किया गया है इसी का परिणाम है कि वन क्षेत्रों में 8 लाख वर्ग किलोमीटर की शुद्ध कमी आई है यह सच में चिंता की बात है

वहीं जर्नल फ्रंटियर्स इन फॉरेस्ट एंड ग्लोबल चेंज में प्रकाशित एक अन्य शोध के अनुसार धरती का केवल 2.8 फीसदी हिस्सा ही अनछुआ रह गया है वहीं धरती पर केवल 3 फीसदी से भी कम हिस्से पर जानवर आज अपनी मूल और प्राकृतिक अवस्था में रह रहे हैं अनुमान है कि जो क्षेत्र आज भी अनछुए हैं उनका केवल 11 फीसदी हिस्सा ही संरक्षित क्षेत्रों के अंदर आता है इनमें से काफी सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो आज भी उनके मूल निवासियों द्वारा संरक्षित हैं जो उनको बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं

ऐसे में यह जरुरी है कि इन संरक्षित क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए यहां रहने वाले मूल निवासियों और उनके प्रथाओं को भी संरक्षित किया जाए, क्योंकि यह लोग ही इन क्षेत्रों के सच्चे प्रहरी है इनके विकास के बिना जैवविविधता को बनाए रख पाना संभव नहीं है। **ललित मौर्य**

इमेजिंग तकनीक से पता लगाया जा सकता है कि भूस्खलन होने की आशंका कहां है

दयानिधि

हर साल भूस्खलन से दुनिया भर में हजारों लोग मारे जाते हैं और संपत्ति का नुकसान होता है। लेकिन वैज्ञानिक अभी भी उन परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें पैदा करती हैं। उन परिस्थितियों के बारे में बेहतर समझ से लोगों को यह अनुमान लगाने में मदद मिलेगी कि भूस्खलन कहां हो सकता है और वह कितना गंभीर होगा।इस बात का पता लगाने के लिए पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के लॉस एंजिल्स में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (यूसीएलए) के प्रोफेसर सेल्गी मून के नेतृत्व में एक अध्ययन किया गया है, जो भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। मून और जेन ली ने यह समझने के लिए एक नई विधि बनाई है, जिसके तहत पता लगाया जा सकता है कि किसी स्थलाकृतिक में तनाव कैसे होता है। यह सभी जानते हैं कि, यह तब होता है जब पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर खिसकती हैं जो ऊपर के भाग को बदलने के लिए पर्याप्त होती हैं, यही भूस्खलन की घटनाओं को प्रभावित करती हैं।

अध्ययन के लिए, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे स्थानों की पहचान करने के लिए 3 डी स्थलाकृतिक तनाव मॉडलिंग नामक एक मौजूदा तकनीक को नए तरीके से विकसित किया। जहां लंबे समय से चट्टानों पर मौसम की मार पड़ रही होती है, जिसका अर्थ है कि वे प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से कमजोर हो गए हैं या टूट गए हैं। उन स्थानों की पहचान करके, मॉडल यह निर्धारित कर सकता है कि कौन से स्थान भूस्खलन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं। यह अध्ययन नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित हुआ है।

खनन का दंश झेल रही महिलाएं पर इसकी चर्चा तक नहीं होती

खनन से जमीन, रोजगार और जैव-विविधता प्रभावित होती है। यह जगजाहिर है। पर खदान के आसपास रहने वाली महिलाएं इससे कैसे प्रभावित होती हैं, इसकी चर्चा तक नहीं होती।

महिलाएं बड़ी संख्या में खनन से जुड़ी हैं। भारत में खानों में काम करने वाली महिला मजदूरों की संख्या का कोई सटीक अनुमान नहीं है। क्योंकि अधिकतर महिला मजदूर ठेके पर काम करती हैं। खदानों के आसपास रहने वाले लोग लगातार प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का खतरा झेल रहे हैं। इसकी दोहरी मार महिलाओं पर पड़ती है। यह जगजाहिर है कि खनन की वजह से जमीन का ह्रास, रोजगार का संकट और जैव-विविधता पर बुरा असर हो रहा है। पर आस-पास रहने वाली महिलाएं भी इससे बुरी तरह से प्रभावित होती हैं, जिसकी चर्चा न के बराबर होती है। देश में 87 तरह के खनिज पाए जाते हैं और इनकी खनन में महिलाएं बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इनकी संख्या को देखते हुए ही 2019 में श्रम मंत्रालय ने भूमिगत खदानों में महिलाओं के काम करने की रोक हटा दी। पर खनन में काम करने वाली महिलाओं के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अधिकतर महिलाएं खदानों में ठेके पर काम करती हैं।

पर यह तो स्पष्ट है कि किसी भी तरह का खदान हो- छोटे हो या बड़े, वैध या अवैध- यहां काम करने वाली महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है।खदानों के आसपास रहने वाले लोग लगातार प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का खतरा झेल रहे हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता रहा है।

क्यों फटते हैं उत्तराखंड में बार-बार बादल ?

विवेक मिश्रा

2013 में विनाशकारी बादल फटने की घटना के बाद 5000 लोगों की जान चली गई थी। इसे देखेते हुए डॉप्टर वेदर रडार जैसी चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने की बात उठी थी जो पूरी मूर्त नहीं हो सकी।

उत्तराखंड में लगातार हो रही तेज या भारी वर्षा के कारण पहाड़ी इलाकों में तबाही हो रही है। इसे आमतौर पर क्लाउडबर्स्ट यानी बदल फटने की घटना कहा जा रहा है। हालांकि क्या यह वाकई बादल फटने की घटना है और यदि है तो क्यों हो रही है? इसका सरल जवाब है कि हम संसाधनों के अभाव में बादलों के फटने यानी कुछ ही घंटों में होने वाली भारी वर्षा का अनुमान लगाने में विफल हो रहे हैं। लेकिन साथ-साथ जलवायु और मौसम की कुछ ऐसी गतिविधियां भी चल रही हैं जो इन घटनाओं की तीव्रता को बढ़ा रही हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में मैरीलैंड विश्वविद्यालय के जलवायु वैज्ञानिक रघु मुर्तुगुडे ने 12 मई, 2021 को बताया कि उत्तराखंट में हाल-फिलहाल होने वाली मौसमी घटनाएं जिसे क्लाउडबर्स्ट के तौर पर जाना जा रहा है वह संबंधित क्षेत्रों को गर्म होने के कारण हो सकते हैं। 3 मई को उत्तराखंड के चार पहाड़ी जिलों रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली में ऐसी घटनाओं ने काफी नुकसान पहुंचाया है। इनमें से नवीनतम बादल फटने की घटना 11 मई की शाम को हुई जिसने टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग शहर में काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों से दो अन्य घटनाओं की भी सूचना मिली है।

हालिया घटनाओं में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि कई इमारतें ढ़ह गईं और सड़कें कीचड़, पानी और मलबे से भर गईं। रघु मुर्तुगडे बताते हैं कि बादल फटने की घटनाएं मौसम की घटनाएं थीं जिनकी किसी परिभाषा के अनुसार भविष्यवाणी करना कठिन है। वह इन घटनाओं के विश्लेषण में कहते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर उत्तर भारत के पश्चिम में बहुत गर्म तापमान की विसंगति है, जो कि असमान्य है। जब अरब की गर्मी कम होती है तो उत्तरी अरब सागर में हवाएं चलती हैं और ओमान के तट पर एक तेज हवा चली है जो गुजरात से सीधे उत्तराखंड में जा रही है। मेरा अनुमान है कि इससे वहां बादल फटने की संभावना बढ़ रही है। मुर्तुगुडे ने कहा कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने उत्तराखंड में सामान्य से अधिक गर्म रहे। "यह भी दबाव को कम करेगा और ऐसी हवाओं को गति देगा।"

अनुसंधान भी मुर्तुगुडे के बयानों का समर्थन करते हैं। मार्च 2017 में जर्नल अर्थ साइंस समीक्षा पत्रिका में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार जून में शुरू होने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारत में क्लाउडबर्स्ट आम तौर पर अधिक आम हैं। वहीं, पूरे क्षेत्र में निम्न-दबाव वाला रिज भी था जिसने बादल फटने की संभावना को बढ़ा दिया था।

क्या है बादल फटना?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) बादल फटने को एक घटना के रूप में परिभाषित करता है, जहां किसी एक क्षेत्र में 20-30 वर्ग किलोमीटर दायरे में एक घंटे के अंतराल में 100 मिलीमीटर बारिश हुई है क्लाउडबर्स्ट तब होता है जब नमी से चलने वाली हवा एक पहाड़ी इलाके तक जाती है, जिससे बादलों के एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ का निर्माण होता है जिसे क्यूमुलोनिम्बस के बादलों के रूप में जाना जाता है। इस तरह के बादल आमतौर पर बारिश, गड़गड़ाहट और बिजली गिरने का कारण बनते हैं। बादलों की इस ऊपर की ओर गति को 'ऑरोग्राफिक लिफ्ट' के रूप में भी जाना जाता है।

ख्यात पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा का कोरोना संक्रमण के बाद निधन

एजेंसियां

1981-1983 तक सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय के पार 5,000 किलोमीटर की एक यात्रा की। इसके बाद तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने हिमालय में पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए कानून पारित किया। वयोवृद्ध पर्यावरणविद् और चिपको आंदोलन के वास्तुकार सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई, 2021 को निधन हो गया। समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उन्हें नोवेल कोविड-19 के संक्रमण के बाद भर्ती कराया गया था।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने उनके पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कामों और उपलब्धियों को याद करते हुए ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेताओं में से एक थे, जो हिमालय में वनों के संरक्षण के लिए लड़ रहे थे। चिपको का अर्थ है 'आलिंगन' या 'पेड़ को गले लगाने वाले' और यह विशाल आंदोलन एक विकेन्द्रीकृत आंदोलन था जिसमें कई अगुवाकार

शामिले थे, आमतौर पर ग्रामीण महिलाएं थीं।

अक्सर आंदोलन करने वाले खुद को पेड़ों से बांध लेते थे ताकि लकड़हारे जंगलों को काट न सकें। इस आंदोलन ने जंगलों के विनाश की रफ्तार को धीमा कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आंदोलन ने 'वनों की कटाई' को जनता के बीच एक संवेदनशील मुद्दा बना दिया। 1981-1983 तक सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय के पार 5,000 किलोमीटर की एक यात्रा का नेतृत्व किया, जो दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ एक बैठक के साथ समाप्त हुआ। इसके बात तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने हिमालय के जंगलों के कुछ क्षेत्रों को पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए कानून पारित किया था।

सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध परियोजना का विरोध करने और भारत की नदी की रक्षा करने के आंदोलन में भी अगुवा थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और गरीबों के अधिकारों के लिए भी काम किया। शांतिपूर्ण प्रतिरोध और अन्य अहिंसक तरीकों के माध्यम से उनके तरीके गांधीवादी थे। चिपको आंदोलन को 1987 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला, जिसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह वैकल्पिक नोबल पुरस्कार उन्हें "... भारत के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, बहाली और पारिस्थितिक रूप से ध्वनि उपयोग के प्रति समर्पण के लिए" दिया गया था। उत्तराखंड के कई जनसंगठनों और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं ने सुंदरलाल बहुगुणा के निधन को अपूर्णीय क्षति करार दिया है। अविरल गंगा, वनों और पहाड़ों का संरक्षण से जुड़ा उनका काम हमेशा याद किया जाएगा।

साभार : डीटीइ

बारिश की बूंद बचाकर हजारों परिवार ने पाई खतरनाक पानी से मुक्ति

माधव शर्मा

राजस्थान के सांभर झील के नजदीक के क्षेत्र में भूजल में खारापन इतना अधिक है कि हैंडपंप भी गल जाते हैं। एक स्थानीय संस्था के दावे के अनुसार इस क्षेत्र के पानी में टीडीएस की मात्रा 5562 है और इसे पीने वालों को तमाम रोग होते रहते हैं। इन क्षेत्रों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग के बूते पानी की समस्या से निजात पाने की कोशिश हो रही है। जयपुर जिले की दूदू पंचायत समिति की चार ग्राम पंचायतों के आठ में से तीन गांवों में घर-घर लगा रेनवाटर हार्वेस्टिंग, बाकी में 90% काम पूरा, टांका की क्षमता 15 हजार लीटर से 22 हजार लीटर तक है।

हरसौली ग्राम पंचायत और आसपास के क्षेत्र में 1991 से काम करने वाली स्वयं सेवी संस्था प्रयास ने अपनी कोशिशों से क्षेत्र की 23 ग्राम पंचायतों में 54 तालाब बनवाये हैं। तालाबों से कुओं का जलस्तर बढ़ा है और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हुआ है। मिलिये 60-साल की प्रेम दरोगा से जो जयपुर जिले की दूदू पंचायत समिति के भोजपुर गांव की रहने वाली हैं। चार साल पहले तक इनको प्रतिदिन आठ किलोमीटर पैदल चलना मजबूरी थी ताकि घर के लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध हो सके। एक किलोमीटर दूर स्थित कुएं पर यह एक दिन में चार बार जातीं थी ताकि इनके परिवार के सात सदस्य जरूरत भर पानी पी लें, भोजन पक जाए और अन्य दैनंदिनी काम

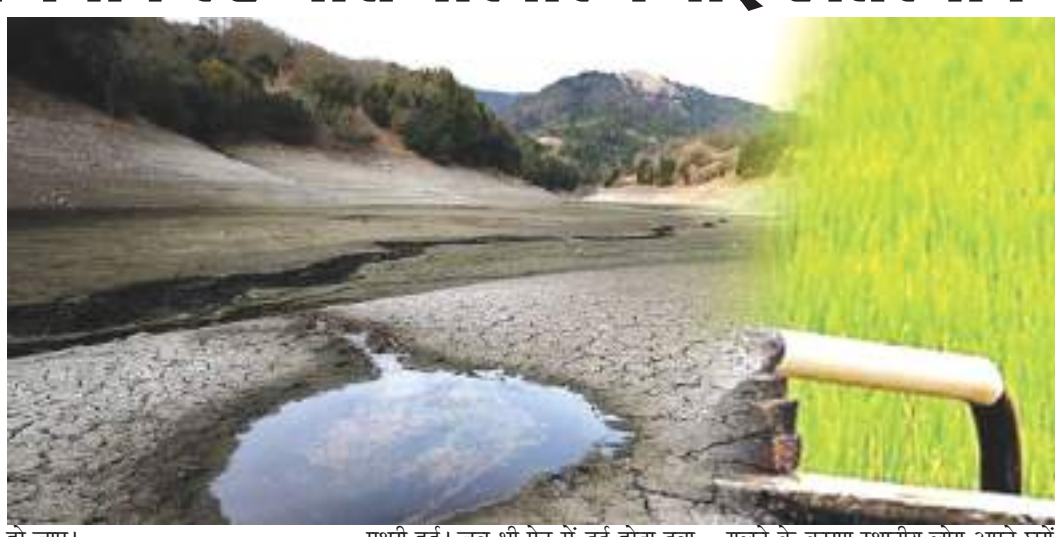

हो जाए।

कमोबेश यही कहानी इनके गांव के 175 परिवारों की थी जो पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लिए संघर्ष करने को मजबूर थे और हर घर की महिलायें दिन के दो-तीन घंटे इस काम में लगाती थीं। बावजूद इसके इनकी समस्याएं कम नहीं होतीं थी। क्योंकि जो पानी मिलता वह भी स्वास्थ्य के लिए मुफीद नहीं होता। इसे पीने से लोगों को कई बीमारियां होती थीं। इलाज में गाढ़े कमाई का पैसा खर्च हो जाया करता था।

इस बारें में प्रेम की देवरानी शायर दरोगा (40) बताती हैं, ''आठ साल पहले मुझे इस खारे-गंदे पानी से पेट में पथरी हुई। जब भी पेट में दर्द होता दवा लेनी होती थी। मेरे आठ साल के बेटे को भी पथरी हो गयी थी। जोड़ों में दर्द भी बना रहता था। इन सब के इलाज में सारी कमाई खर्च हो जाती थी।

इन इलाकों में क्यों हैं ऐसी मुसीबत?

इसकी वजह है आस-पास के मौजूद पानी की गुणवत्ता। सांभर झील के नजदीक होने से आसपास के 80-100 किलोमीटर के क्षेत्र में भूमिगत जल बहुत ही खारा है। पानी में लवणता इतनी है कि यहां लगाए गए हैंडपंप तीन साल से ज्यादा नहीं चल पाते। उनका लोहा नमक की वजह से गल जाता है। यहां लगे हैंडपंप सरकारी हैं। गलने के कारण स्थानीय लोग अपने घरों में ट्यूबवेल लगाने से बचते हैं।एक स्वयंसेवी संस्था प्रयास केन्द्र ने इन गांवों में पानी की जांच कराई तो उसके नतीजे काफी चौंकाने वाले आए। पानी में अधिकतम टीडीएस 500 मिलीग्राम/लीटर ही तय है। जबकि यहां के भूमिगत जल में टीडीएस चार से 11 गुना तक अधिक पाया गया। आसपास के गांवों में भूमिगत जल में टीडीएस की मात्रा 2 हजार से 5562 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाई गई। इसी तरह टोटल हार्डनेस 200 की जगह 400 से 900 मिलीग्राम प्रति लीटर तक मिला। कैल्शियम भी तय मात्रा (75 मिलीग्राम/लीटर) के स्थान पर 400 मिलीग्राम/लीटर, मैग्निशियम (30 मिलीग्राम/लीटर) की जगह 141 मिलीग्राम/लीटर, क्लोराइड (250 मिलीग्राम/लीटर) 2558 मिलीग्राम/लीटर, सल्फेट (200 मिलीग्राम/लीटर) नहीं होकर 1022 मिलीग्राम/लीटर तक पाया गया है। इसके अलावा पानी में फ्लोराइड, सोडियम और सिलिका भी तय मात्रा से ज्यादा मिले हैं।

बारिश से समाधान?

पानी की समस्या खत्म करने के लिए शुरूआत में संस्था ने दूदू पंचायत समिति की 56 ग्राम पंचायतों में से 23 में तालाब बनाने शुरू किए। 2011 तक 54 तालाब पूरे क्षेत्र में बनाए गए, बंशी बताते हैं।

इनका दावा है कि इन तालाबों से 23 ग्राम पंचायतों के करीब 1500 परिवारों की 92 हजार की आबादी की कृषि उपज बढ़ी है। इनके एक लाख से ज्यादा पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध हुआ है। इससे पहले इस क्षेत्र में कुल खेती में से सिर्फ 16% पर ही सिंचाई होती थी। जो कुओं पर निर्भर थी। हालांकि इससे लोगों के पीने के पानी का समाधान नहीं हुआ। इसीलिए 2011 में घर-घर में रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का विचार किया गया, इसी रुफ़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग ने इस इलाके के लोगों की सालों से चली आ रही समस्या से निजात दिला दी। लोगों को काफी राहत मिली।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।